

‘युवा मेहनत करें, राज्य सरकार उनके सपनों को पूरा करेगी’

शेखावाटी दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भजनलाल ने मंडावा मुकुन्दगढ़ व झुंझुनूं में सभाओं को संबोधित किया

■ मुख्यमंत्री ने कहा, लोग कहते हैं कि इतनी भीषण गर्मी में आप दौरे कर रहे हैं। मैं किसान का बेटा हूँ और किसान के बेटे को गर्मी नहीं लगती।

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि झुंझुनूं के नेता चुनावों के समय यमुना जल को याद करते थे लेकिन केन्द्र व राज्य सरकारों में महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए शेखावाटी के लिये कुछ काम नहीं किया।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावाटी क्षेत्र की तीन दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन मंडावा, मुकुंदगढ़ व झुंझुनूं में जनसभाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, यमुना जल समझौते पर तेजी से कार्य हो रहा है और इसकी प्रवाह प्रणाली की डीपीआर बनाने का काम प्रारंभ हो चुका है।

सरकारों ने महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी शेखावाटी के लिए कुछ काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता किया। उसके बाद कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार में आते ही वह शेखावाटी यमुना जल समझौते को रद्द कर देंगे। मैं आपके बीच यह विश्वास दिलाने आया हूँ कि यमुना जल समझौते पर तेजी से कार्य हो रहा है और इसकी प्रवाह प्रणाली की डीपीआर बनाने का काम प्रारंभ हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झुंझुनूं में कांग्रेस नेता चुनावों के समय यमुना जल को याद करते थे लेकिन केन्द्र व राज्य

बेटा हूँ और किसान के बेटे को घूप नहीं लगती। उन्होंने शेखावाटी के लोगों की जिजीविषा की तारीफ करते हुए कहा कि यहां किसान खेत में काम करता है और किसान का बेटा यानी जवान सीमा पर देश की रक्षा करता है।

नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मुकुंदगढ़ में आयोजित स्वागत एवं आभार सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शेखावाटी किसानों और किसानों की धरती है। किसान बड़ी उम्मीद के साथ अपने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं ताकि वह नौकरी पाकर उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा मगर कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक से उनके सपनों को चकनाचूर हुए। हमारी

सरकार के 16 महीने में एक भी पेपरलीक नहीं हुआ है।

कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, नगरीय विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झावर सिंह खर्रां, विधायक विक्रम सिंह जाखल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।

झुंझुनू टोल प्लाजा पर आयोजित आभार सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारा किसान समृद्ध होगा तो प्रदेश भी उन्नत और खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि हमारा वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य है। हम किसानों को अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता भी बनाना चाहते हैं।

अमेरीका में ट्रंप के विरोध में प्रदर्शन जारी है

वाशिंगटन, 20 अप्रैल। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के खिलाफ इस महीने विरोध प्रदर्शन करने के लिये हजारों प्रदर्शनकारियों ने पूरे देश में सड़कों पर उतरकर उनके हालिया कार्यों की निंदा की और उन्हें अमेरिका के मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए खतरा बताया।

बीबीसी के अनुसार, “50501” के नाम से मशहूर ये प्रदर्शन “50 विरोध, 50 राज्य, 1 आंदोलन” के लिए हुए, जो अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध की शुरुआत की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर हुए। न्यूयॉर्क से लेकर सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन, शिकागो, रोड आइलैंड, मैरीलैंड, विस्कॉन्सिन, टेनेसी, साउथ कैरोलिना, मैनेहटन, बॉस्टन जैसे कई अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राष्ट्रपति के विरोध में प्रदर्शन हुये।

शनिवार के विरोध प्रदर्शनों में ट्रम्प की कई कार्रवाइयों को संबोधित किया गया, जिनमें सरकारी दक्षता विभाग, अमेरिकी सरकारी नौकरियों और अन्य खर्चों में कटौती करने की पहल और अल सैलवाटर के नागरिक एग्रेसो गार्सिया की वापसी के लिए प्रशासन की अनिच्छा शामिल है।

अमृतपाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुए कहा कि देश में सिखों के लिए अलग कानून चल रहा है। तरसेम सिंह ने कहा कि अमृतपाल पर एनएसए बढ़ाने का फैसला लोकतंत्र की ध्वजिया उड़ाने जैसा है। सांसद बनकर अमृतपाल लोगों की आवाज उठाना चाहता है, लेकिन उस पर एनएसए लगाकर उसे रोका जा रहा है। यह सब कुछ केंद्र व पंजाब सरकार मिलकर कर रही है।

तरसेम सिंह ने कहा कि अमृतपाल के राजनीति में आने से सरकारें डरी हुई हैं। सरकारें लोगों को मजबूर कर रही हैं कि वे गलत रास्ता अपनाएँ। पंजाब में पिछले दो वर्षों में अपराध बढ़ा है। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हत्या या अपराध न हुआ हो।

ए.सी.बी. को 1 9 स्थानों पर सुपरिन्टैन्डेंट इंजीनियर जांगिड़ की 5 4 सम्पत्तियां मिलीं

पी.एच.ई.डी. के एस.ई. अशोक जांगिड़ पर कार्यवाही करने वाली ए.सी.बी. टीम में 250 लोग थे

■ ए. सी. बी. को प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक जांगिड़ व उसके परिवार के नाम 22 बैंक खाते हैं। इनमें 21 लाख रुपये मिले हैं।

हैं। एसीबी को कुल 19 स्थानों पर 54 अचल सम्पत्तियां खरीदने व निर्माण में करोड़ों रुपए लगाने के सबूत मिले हैं। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार अशोक जांगिड़ के जयपुर शहर, पावडा (कोटपूतली), मौजामाबाद (जयपुर), उदयपुर स्थित खान एवं भू-विज्ञान विभाग के ज़ोन ऑफिस, झाड़ोल (उदयपुर) के कोच्छला, जावद स्थित खनिज लीज, अजमेर, मालपुरा (टोंक) के विभिन्न

ठिकानों के साथ-साथ पीएचईडी कार्यालय बांसवाडा, टोंक, अजमेर, जयपुर व उप पंजीयक कार्यालय पावडा, मौजामाबाद में टीमों ने सच किया है। इस कार्रवाई में 250 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे। उदयपुर स्थित खान एवं भू-विज्ञान विभाग के ज़ोन ऑफिस में टीम ने जांगिड़ के परिवार के सदस्यों के नाम पर मिले माइंस के दस्तावेजों को खंगाला। एसीबी को गोपनीय सूचना मिली थी कि जांगिड़ ने राजकीय सेवा में आने के बाद 11.50 करोड़ रुपए की आय अर्जित की। यह उनकी मूल आय से 161 प्रतिशत अधिक है।

आरोपी और उनके परिवार के नाम से 22 बैंक खाते हैं। इनमें 21 लाख रुपए मिले हैं। बेटे और बेटों की स्कूली शिक्षा, कोचिंग एवं उच्च शिक्षा में करीब 30 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

‘जनेऊ उतारो, ...

मोदी सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सरकारी कॉलेज में सीट दे। छात्र की शिकायत के बाद बीदर जिला प्रशासन ने घटना की जांच शुरू की। बीदर के उपायुक्त ने कॉलेज के प्राचार्य चंद्र शेखर बिरादर और स्टाफ सदस्य सतीश पवार को आगे की जांच तक निलंबित करने का निर्देश दिया।

कॉलेज के प्रबंधन साई दीपा एजुकेशन एंड वैरिटेबल ट्रस्ट ने 19 अप्रैल को एक आपातकालीन बैठक की और औपचारिक रूप से दोनों अधिकारियों को निलंबित करने का निर्णय लिया। इस घटना पर छात्र के परिवार और जनता की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएँ सामने

आई है। सुचित्रत की माँ नीता कुलकर्णी ने अपने पुत्र के साथ किए गए व्यवहार पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “वह बहुत दुखी था। उसे अपना जनिबारा छोड़ने या घर जाने के लिए कहा गया था।” उन्होंने कहा, “हम अधिकारियों से न्याय सुनिश्चित करने की अपील करते हैं। या तो फिर से परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए या मेरे पुत्र को वित्तीय सहायता के साथ एक अच्छे कॉलेज में सीट दी जानी चाहिए।” कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) ने अभी तक इस मामले पर औपचारिक बयान जारी नहीं किया है।

हैरल्ड मामले में जिस परिवार को बदनाम करने का प्रयास किया गया, उसके घर का हर सदस्य आजादी के आंदोलन में जेल में रहा। आजादी के पहले आनंद भवन और स्वराज भवन जैसी संप्रति देश को समर्पित कर दी थी। इंदिरा गांधी जी देश के लिए शहीद हुईं, राजीव गांधीजी शहीद हुए। पिछले 11 सालों से कांग्रेस और विपक्षी दलों के साथ मोदी सरकार दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही है। सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी इसलिए निशाने पर हैं क्योंकि वह कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं। खड़गे ने कहा, दूसरे ताकतवर विपक्षी नेताओं पर इसी तरह फर्जी मामले चलाए जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, उसका केस बंद कर दिया जाता है। इनकी शर्म आनी चाहिए कि 10 सालों में ईडी ने 193 नेताओं पर केस किया लेकिन केवल दो मामले को वे साबित कर पाये। जब चाहते हैं घंटों पृछताछ करके ईडी के लोग फखरे फैलाते हैं।

फर्जी कार्डियॉलजिस्ट व अपोलो अस्पतास के खिलाफ एक और केस

बिलासपुर, 20 अप्रैल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष पं. राजेन्द्र शुक्ल की मौत के सन् 2006 के मामले में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर और अपोलो अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार डॉ. नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जान केम एवं अपोलो प्रबंधन के खिलाफ शिकायत मिली थी। यह शिकायत डॉ. प्रदीप शुक्ला ने बिलासपुर जिले के सरकंडा थाने में दी थी। डॉ. नरेंद्र पर आरोप है, कि उन्होंने फर्जी डिग्री पर आधार पर इलाज किया और लापरवाही के कारण मरीज की जान चली गई।

शिकायत पर डॉक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले में अपोलो अस्पताल प्रबंधन को भी आरोपी बनाया गया है।

अस्पताल प्रबंधन पर आरोप है, कि बिना जांच के फर्जी डॉक्टर को नौकरी पर रखा और मरीज की जिंदगी खतरे में डाल दी। आरोपी डॉक्टर वर्तमान में दमोह पुलिस की हिरासत में है।

जम्मू कश्मीर में बादल फटने से 3 मरे

रामबन जिले में कई जगह लैंडस्लाइड हुई, जिसमें सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं

श्रीनगर, 20 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। रामबन जिले के सेरी बागना इलाके में रविवार सुबह बारिश के बाद बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने करीब 100 लोगों को रेस्क्यू किया। सूत्रों ने बताया कि बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ का मलबा गांव की तरफ आ गया, और कई लोग और घर उसकी चपेट में आ गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

उधर, रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह भूस्खलन हुआ है। इसकी वजह से जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। किश्तवाड़-पहर मार्ग भी बंद है। यहां वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। अधिकारियों ने मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे पर सफर करने की अपील की है।

अधिकारियों ने रविवार को बताया

■ बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ का मलबा गाँव की तरफ आ गया, कई लोग व घर इसके चपेट में आ गये।

कि रामबन जिले में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग पृथ्याल, सेरी और अन्य इलाकों में बंद हो गया। इसके अलावा, बादल फटने से धर्मकुंड क्षेत्र में तीन लोगों की मौत हो गई।

भारी बारिश और भूस्खलन के कारण त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्वआरटी) और पुलिस की ओर से पूर्ण महैया अभियान नहीं चलाया जा सका। जिले में बाढ़ से निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ, तथा बाढ़ के

कारण शहर में अवरुद्ध सड़कों पर वाहन फंस गए हैं। कटुआ-उधमपुर से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, रामबन क्षेत्र और आसपास के इलाकों में रातभर तेज ओलावृष्टि, भूस्खलन और तेज हवाएँ चलीं। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, तीन लोगों की मौत हुई है और कुछ परिवारों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। मैं डिप्टी कमिश्नर बसीर-उल-हक चौसरी के साथ लगातार संपर्क में हूँ।

डॉ. सिंह ने पोस्ट में कहा कि प्रशासन की तत्परता से कई जानें बचीं। हर तरह की मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा, हर तरह की राहत, चाहे वह वित्तीय हो या अन्य, मुहैया कराई जा रही है। डीसी को सूचित किया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सांसद के निजी संसाधनों से भी जो कुछ भी आवश्यक होगा, वह मुहैया कराया जा सकता है। अनुरोध है कि घबराएं नहीं। हम सब मिलकर इस प्राकृतिक आपदा से निपटेंगे।

मुर्शिदाबाद में बाप-बेटे की हत्या के मामले में एक और गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी जियाउल शेख 12 अप्रैल को हिंसा की घटना के बाद से फरार था

कोलकाता, 20 अप्रैल। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में एक व्यक्ति और उसके बेटे की हत्या के मुख्य आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि क्षमशेरगंज के जाफराबाद में दो लोगों की हत्या के मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान जाफराबाद के पड़ोसी गांव सुलिताला रुपबापारा निवासी जियाउल शेख के रूप में हुई है। वह 12 अप्रैल को अपराध की घटना के बाद से फरार था।

उन्होंने बताया कि शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शनिवार को उरार दिनापुर जिले के चौपड़ा में उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया।

■ पुलिस ने बताया कि 12 अप्रैल को मृतक के घर जियाउल शेख की मौजूदगी के सभी सबूत, सीबीटीटी फुटेज तथा मोबाइल फोन लोकेशन आदि उनके पास हैं।

अधिकारी ने बताया, यह व्यक्ति मुख्य आरोपियों में से एक है, जिसने 12 अप्रैल को मृतक के घर पर तोड़फोड़ करने और हथगोबिंदो दास, उसके बेटे चंदन दास की हत्या करने के लिए भीड़ को प्रेरित किया और साजिश रची। उन्होंने बताया कि

पुलिस के पास 12 अप्रैल को अपराध स्थल पर उसकी मौजूदगी साबित करने के लिए सभी सबूत, सीसीटीवी फुटेज और उसके मोबाइल फोन टावर की लोकेशन मौजूद है। इससे पहले पुलिस ने दो भाइयों कालू नादर और दिलदार और इंजमाम उल हक को दोनों की हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तीसरे आरोपी को जाफराबाद के पड़ोसी गांव सुरीपारा से पकड़ा गया। अधिकारी ने बताया कि हमने मुर्शिदाबाद हिंसा मामलों में 100 से अधिक एफआईआर दर्ज की हैं। अब तक 276 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्ञातव्य है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन को लेकर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में कम से कम तीन लोग मारे गए थे।

कर्नाटक के पूर्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच करने पर पता चला कि उनकी हत्या की गई है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पत्नी ने ही पुलिस को फोन करके हत्या की जानकारी दी थी, लेकिन जब पुलिस टीम उनके घर पहुंची तो उन्होंने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उनके शव पर चोट के निशान भी मिले हैं।

यू. पी. विधान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऐलान करते हुए कि 2027 के चुनाव में सपा और कांग्रेस साथ-साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। प्रयागराज में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, राज्य से भाजपा को उखाड़ फेंकेगा।

हाईकोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है, किसी भी व्यक्तिगत लाभ या व्यावसायिक उपयोग के लिए सरकार या पूर्व राजपरिवार द्वारा हस्तांतरित नहीं की जा सकती।

मुद्दा यह नहीं है कि, कोविड के इन्तजामात में कुछ अरबों रुपये का भ्रष्टाचार...



उदयपुर में कोरोना काल में बनाये गये आई. सी. यू., पी.आई. सी. यू. का अन्य रोगों के इलाज के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें न्यूरो, कैंसर, मेडिकल से संबंधित रोग शामिल हैं। इन आई.सी.यू., पी.आई.सी.यू. का बदलाव संभवतः इसलिये किया गया है क्योंकि यहां पर भी मायवर्डों की पालना नहीं की गई है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पुष्टि करने के लिये राष्ट्रदूत के पास कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं हैं। तीसरा उदाहरण उदयपुर का है, जहाँ कोरोना काल के दौरान एम.बी. चिकित्सालय में नवनिर्मित एक भवन को कोरोना रोगियों के लिए गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में परिवर्तित कर दिया गया था। एम बी चिकित्सालय परिसर में स्थित इस इकाई को पृथक इकाई के रूप में संचालित करते हुए यहां न्यूरो, कैंसर, मेडीसन एवं

सर्जिकल से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार किया जा रहा है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डा.विपिन माथुर इस इकाई के पृथक चिकित्सा औषधिक का कार्य भी देख रहे हैं। कोरोना काल में यहां लगाए गए सभी उपकरण एम.बी.चिकित्सालय में नवनिर्मित आई.सी.यू. में शिफ्ट कर दिए गए हैं वहीं स्वाइन फ्लू वाईड, मेडीसन वाईड एवं चर्म रोग के उपर स्थित अस्थायी कोरोना गहन चिकित्सा वाईड को अब सामान्य वाईड में परिवर्तित

किया जा चुका है।

इस शृंखला में, पहले प्रकाशित दस्तावेजों के अनुसार, उदयपुर में 50 बेड का आई.सी.यू. और 20 बेड का एन.आई.सी.यू. बनाने के लिये 750 लाख और 307 लाख रुपये की राशि एस.डी.आर.एफ. फंड से राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उपयोग करने के आदेश दिये थे।

इसी प्रकार, बीकानेर में कोविड महामारी के दौरान, प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, 50 बेड के आई.सी.यू. और 10 बेड के एन.आई.सी.यू. की स्थापना के आदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये, जिसमें एस.डी.आर.एफ. फंड से 750 लाख रुपये और 167 लाख रुपये की राशि मुहैया कराने के आदेश दिये। हैरानी की बात है कि प्रिंस विजय सिंह मैमोरियल (पी.बी.एम.)

अस्पताल परिसर में आई.सी.यू. का निर्माण किया गया था। इस अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टरों से जब बात की गई तो उन्होंने नाम ना बताते की शर्त पर बताया कि इस आई.सी.यू. को कोविड के बाद बंद कर दिया गया। बाद में इसे जनाना अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। यहां गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि पी.बी.एम. अस्पताल परिसर में सरकारी आदेशों के अनुरूप निर्माण कार्य करने के लिये इस्तेमाल होने वाली बजरी भी अनुमत नहीं थी। जैसा कि



बीकानेर में इन आई.सी.यू., पी.आई.सी.यू. में महिला चिकित्सालय खोल दिया गया है, जहां पर महिला मरीजों की आवाजाही कम ही होती है, इसलिये यह अस्पताल बंद ही रहता है।

विदित है कि सरकारी निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली बजरी के लिए अनुबंधित कंपनियों को बजरी खनन के लिये “शॉर्ट टर्म परमिट” (एस.टी.पी.) लेना जरूरी होता है, परंतु महामारी के दौरान राज्य सरकार के खनन विभाग द्वारा कोई भी नई एस.टी.पी. जारी नहीं की जा रही थी, जिससे स्पष्ट है कि इस आई.सी.यू. के निर्माण में भी किसी तरह की एस.टी.पी. नहीं ली गई।

पांचवा उदाहरण देखें तो,

आरबीएम हॉस्पिटल में लगाए गए कोरोना बैड अब भी वॉर्ड में संचालित हो रहे हैं जिसमें विभिन्न रोगों के मरीज भर्ती रहते हैं। अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना के समय आर्थिक व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टर आपदा प्रबंधन से 30 लाख का लोन एवं कलेक्ट्रेट से 5 लाख का लोन लिया था। 21 जनवरी 2023 को अस्पताल प्रबंधन ने 30 लाख का लोन जिला कलेक्टर आपदा प्रबंधन को चुका दिया।

हालांकि, प्राप्त दस्तावेजों से साफ जाहिर है कि भरतपुर में पहले तो 10 बैड का पी.आई.सी.यू. बनाया गया जिसमें 167 लाख रुपये का खर्चा एस.डी.आर.एफ. फंड से किया गया। और फिर 20 बिस्तर का आई.सी.यू. भी बनाया गया जिसमें 456 लाख रुपये का खर्चा आया।

जैसा कि विदित है कि सरकारी निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली बजरी अनुबंधित कंपनियों को बजरी खनन के लिये “शॉर्ट टर्म परमिट” (एस.टी.पी.) लेना जरूरी होता है, परंतु महामारी के दौरान राज्य सरकार के खनन विभाग द्वारा कोई भी नई एस.टी.पी. जारी नहीं की जा रही थी, जिससे स्पष्ट है कि इस आई.सी.यू. के निर्माण में भी किसी तरह की एस.टी.पी. नहीं ली गई।



भरतपुर में आर बी एम हॉस्पिटल में पुरानी बिल्डिंग में लगाए गए बेड अब वर्तमान में नहीं हैं, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर अब नई बिल्डिंग बनाई जा रही है।

छठा उदाहरण, सीकर में डॉ. के.के. अग्रवाल ने बताया कि कोविड के समय एन.आई.सी.यू., पी. आई. सी. यू. और आई. सी. यू. जनाना अस्पताल और श्री कल्याण अस्पताल में बनाए गए थे, उन्हें नष्ट कर दिया है। उनकी जगह नया भवन बन रहा है। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार सीकर में 20 बैड का आई.सी.यू. और 12 बैड का एन.आई.सी.यू. बनाने के निर्देश चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दिये थे, जिनमें क्रमशः 456 लाख रुपये और

200 लाख रुपये एस.डी.आर.एफ. फंड से खर्च किये गये। ऐसी ही कहानी पाली, बाडमेर, भीलवाडा, डूंगरपुर में भी देखी गई। दस्तावेजों को देखने से जाहिर होता है कि पहले यह स्वीकृति मेडिकल उपकरणों को खरीदने के लिये दी गई थी, जो नियमों में अनुमत है, परंतु इस फंड का उपयोग कुछ निजी चुनी कंपनियों को अस्वीकृत निर्माण कार्य करने के लिये दिया गया। (क्रमशः)